गहलोत सरकार के घोटाले में लिप्त मंत्री-अफसर आज जेल में हैं- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने कोटा और पाली में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया

-कार्यालय संवाददाता-

कोटा/पाली, 8 सितम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को कोटा और पाली में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया। उन्होंने निकाय चुनावों में भाजपा की जीत का आव्हान करते हुए ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का आव्हान किया।

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए जल जीवन मिशन घोटाले, भ्रष्टाचार, पेपर लीक और तुष्टिकरण पर चुनाव सभा में सवाल खड़े किए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को कोटा में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में भव्य रोड शो किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटा के कैथूनीपोल चौराहे पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए जल जीवन मिशन घोटाले, भ्रष्टाचार, पेपरलीक और प्रदेश में तुष्टिकरण को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे, तब उनकी सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ में डूबी रही, परंतु गहलोत ने आंखें मूंदे रखीं। कांग्रेस के घोटालों में लिप्त मंत्री और अधिकारी आज जेल में हैं।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोगों की मैथमेटिक्स कमजोर है तो मेरे पास आ जाओ। आपका ट्यूशन भी लगवा दूंगा। अभी तक ढाई साल हुआ है, अभी भी ढाई साल बाकी है। यह आंकड़ा अभी लाखों में पहुंच रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शाम 4 बजे पाली से कोटा एयरपोर्ट पहुंचे। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के घर पर उनसे मिलने गए। एयरपोर्ट पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर, विधायक संदीप शर्मा, कल्पना देवी, शहर भाजपा अध्यक्ष राकेश जैन, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री स्वागत किया।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पाली में सूरजपोल बाजार से सोमनाथ मंदिर, सर्राफा बाजार, फतेहपुरिया बाजार, पानी दरवाजा होते हुए, सिंधी कॉलोनी तक रोड शो निकाला। मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले भाजपा ने सूरजपोल चौराहे से लेकर पूरे बाजार व सिंधी कॉलोनी को भाजपा के झंडों से सजाया। सुबह 10 बजे से 65 वार्डों में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ भाजपा के झंडे लहराते सूरजपोल चौराहे पर एकत्रित हुए। दोपहर करीब 1 बजे मुख्यमंत्री का काफिला सूरजपोल पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री सीधे रथ पर चढ़े, उनके साथ सांसद पीपी चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख भी थे।

सत्ताइस साल पहले रिटायर जिला जज को पेंशन परिलाभ देने के आदेश

जयपुर, 8 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने 27 साल पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से रिटायर याचिकाकर्ता को दो सप्ताह में पेंशन सहित, अन्य परिलाभ ब्याज सहित अदा करने को कहा है। जस्टिस संजीव प्रकाश

■ राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने दो सप्ताह में ब्याज सहित भुगतान के निर्देश दिए।

शर्मा और जस्टिस चन्द्र शेखर शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश मातादीन गर्ग की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि यदि किसी दस्तावेज पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर जरूरी हैं तो उसकी उम्र को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्री अधिकारी को उनके निवास पर भेजकर हस्ताक्षर कराए जायें। अदालत ने कहा कि यदि तय अवधि में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो याचिकाकर्ता को 12 फीसदी ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा और इस अतिरिक्त राशि की वसूली संबंधित अधिकारी से की जाएगी।

याचिका में अधिवक्ता सोगत रॉय ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता मार्च, 1999 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से रिटायर हुआ था। रिटायर होने के दो साल तक सरकारी भवन खाली नहीं करने पर संपदा निदेशक से हाईकोर्ट प्रशासन को पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि उसकी ग्रेच्युटी में से 57 हजार 454 रुपए काटकर शेष राशि जारी कर दी जाए। इसके बावजूद शेष बकाया राशि और पेंशन नहीं दी गई। रने को कहा है।

ब्रिक्स देशों के साथ रुस का 90 प्रतिशत व्यापार डॉलर में नहीं होता

रुस ने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ब्रिक्स देशों की राष्ट्रीय मुद्रा का उपयोग हो रहा है

नई दिल्ली, 08 सितंबर। रूस का कहना है कि ब्रिक्स देशों के साथ उसका 90 प्रतिशत व्यापार राष्ट्रीय मुद्राओं में हो रहा है। इसका प्रमुख कारण अमेरिका की ओर से रूस के लिए डॉलर आधारित वित्तीय प्रणाली तक पहुंच को प्रतिबंधित करना है। रूस अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर डॉलर के प्रयोग के विरोध में नहीं है। असल में अमेरिका की नीतियां ही डॉलर को फायदेमंद बनाने से रोक रही हैं। इसी के चलते रूस को अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं का अधिक उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

स्पूतनिक इंडिया की ओर से नई दिल्ली के इंडिया हैबिटैट सेंटर में वीडियो कांफ्रेंसिंग से आयोजित पत्रकार वार्ता में क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने उक्त बातें कहीं।

■ क्रैमलिन प्रवक्ता ने कहा कि ब्रिक्स किसी के खिलाफ बनाया गया समूह नहीं है, बल्कि यह अपने राष्ट्रीय हितों को मिलकर साधने का मंच बनकर उभरा है।

पत्रकार वार्ता आगामी ब्रिक्स शिखर वार्ता और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के संबंध में थी। पेस्कोव ने कहा कि ब्रिक्स किसी के खिलाफ बनाया गया समूह नहीं है, बल्कि यह अपने राष्ट्रीय हितों को मिलकर साधने का मंच बनकर उभरा है। इसका उद्देश्य पश्चिम के साथ टकराव नहीं है। वहीं, डॉलर से जुड़े प्रश्न के उत्तर में पेस्कोव ने कहा कि अगर वे हमें अपना पैसा (डॉलर) इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो हम अपना पैसा (राष्ट्रीय मुद्रा) इस्तेमाल करेंगे। हम किसी भी प्रकार की डॉलर-विरोधी नीति का समर्थन नहीं करना चाहते। हम बस वही कर रहे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए सबसे उपयुक्त है।

प्रवक्ता ने कहा कि ब्रिक्स की विचारधारा में बहुध्रुवीय विश्व की अवधारणा प्रमुखता से शामिल है। हालांकि उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा कि कुछ शक्तियां एक ध्रुवीय विश्व को फिर से स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं। इसके लिए खतरनाक तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। वहीं, वैश्विक बहुमत बहुध्रुवीय विश्व के पक्ष में है और भारत इस दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है।

प्रधानमंत्री की मुंबई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शामिल हो रहे हैं, इसलिए कार्यक्रम स्थल पर जबरदस्त पुलिस व्यवस्था की गयी है। इसी जगह पर सिक्योरिटी चेक के दौरान दोनों युवक संदिग्धावस्था मिले। सुरक्षा एजेंसियों को उन पर शक हुआ और उन्होंने तुरंत दोनों को हिरासत में ले लिया। उनमें से रोहन पारेख ने खुद को पीएमओ का अफसर बताया और परिचय पत्र दिखाया। लेकिन जांच के दौरान रोहन का परिचय पत्र बोगस पाया गया, जबकि उसके साथ के व्यक्ति के पास पिस्तौल मिला। इसलिये दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

महेश्वरी स्कूल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रबंधन का कहना है कि वे अपने स्तर पर भी मामले की जांच कर रहे हैं और दोषी छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पहली बार लग रहा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

समर्थक लोग, खास तौर पर आईआरजीसी, बातचीत की किसी भी संभावना को रोक रहे हैं। कुल मिलाकर, कट्टरपंथी इस बात के खिलाफ हैं कि ऐसा दिखाई दे कि ईरान अमेरिका को कोई रियायत दे रहा है। मुद्दे स्पष्ट हैं। अमेरिका होरमुज के मामले में पहले जैसी स्थिति चाहता है। इसका मतलब है कि यह संकरा जलडमरूमध्य फिर से एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग बने और उस पर ईरान का नियंत्रण न रहे।

अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी रियायत चाहता है और चाहता है कि इसे दोबारा शुरू न किया जाए। और अंत में, ईरान प्रतिबंधों में तत्काल राहत और अरबों डॉलर की फ्रीज़ की गई रकम को जारी करने की मांग कर रहा था। इन मुद्दों में से कई पर अमेरिका जून में हुए समझौते में काफी हद तक सहमत हो गया था, लेकिन ईरान ने हमले करके और जानबूझकर समझौते का उल्लंघन करके उस समझौते को खत्म हो जाने दिया। इसलिए कोई हैरानी नहीं कि डॉनल्ड ट्रंप जून के समझौते को खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब वह समझौता अस्तित्व में नहीं है। अमेरिका अब धैर्य के साथ इंतजार करने की रणनीति अपना रहा है और देख रहा है कि ईरान इस लगातार बढ़ते दबाव को कितने समय तक झेल सकता है, जो उसकी अर्थव्यवस्था का दम घोंट रहा है और आम लोगों को लगातार बढ़ती और असहनीय होती जा रहीं मुसीबतों में डाल रहा है।

मुख्यमंत्री आज ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्वागत करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए स्थानीय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पहले चरण के मतदान के बीच होने वाला मुख्यमंत्री का यह रोड शो भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जयपुर के पुराने शहर में रोड शो के जरिए पार्टी अंतिम दौर में चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने का प्रयास करेगी।

विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में नशा मुक्ति अभियान चलायेगी -भाजपा

राज्य की सभी 117 सीटों से गुजरने वाली यात्रा की शुरुआत नितिन नबीन 18 सितम्बर को करेंगे

नई दिल्ली, 08 सितंबर। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य में नशे के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी 18 सितंबर से पूरे पंजाब में नशा विरोधी यात्रा निकालेगी। यह यात्रा राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी। इस अभियान की शुरुआत भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन करेंगे।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस अभियान के जरिए भाजपा नशे के खिलाफ अपनी ज़ीरो टॉलरेंस नीति को जनता के सामने रखेगी।

■ दो सप्ताह चलने वाली यात्रा में भाजपा के कई बड़े नेता शामिल होंगे। समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह के आने की संभावना बताई जा रही है।

पार्टी लोगों से वादा करेगी कि अगर उसे इस बार सत्ता मिलती है तो नशे की समस्या को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। यात्रा के दौरान नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।

करीब दो सप्ताह चलने वाली इस यात्रा में भाजपा के कई बड़े नेता शामिल होंगे। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सहित वरिष्ठ नेताओं के यात्रा में शामिल होने की संभावना है। इसके साथ, इन यात्राओं के समापन समारोह में गृहमंत्री अमित शाह के आने की संभावना जताई जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का यह अभियान पंजाब में नशे के मुद्दे को चुनावी बहस के केन्द्र में लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

इस बीच मंगलवार को भाजपा ने गुलजार सिंह का मुद्दा उठाया। गुलजार सिंह ने पंजाब में नशीले पदार्थों की समस्या को लेकर पंजाब सरकार के वित्त मंत्री के समक्ष सवाल उठाया था। गुलजार सिंह ने मृत्यु से पूर्व सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में मंत्री के डर के कारण जहर खाने का दावा किया था तथा गांव की पंचायत के कुछ लोगों के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाए थे।

गहलोत, आशा लगाए ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिम्मेदारी संभालने के साथ राजस्थान में भी राजनीतिक समीकरण बदलेंगे।

रंधावा पंजाब से सांसद हैं। वे जाट सिख हैं और राजस्थान कांग्रेस के जाट पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा से उनके मजबूत संबंध हैं।

हाल ही में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की थी।

गहलोत ने पायलट को दबाए रखने और यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वे राजस्थान के सत्ता ढांचे से बाहर रहें।

लेकिन अब, जब सचिन पायलट को एक महत्वपूर्ण चुनावी राज्य की बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो गहलोत इस बात से बेहद नाराज़ लग रहे हैं कि उन्हें दरकिनार कर दिया गया है।

गहलोत को उम्मीद थी कि के सी वेणुगोपाल, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक और अन्य नेता उन्हें फिर से राजनीतिक रूप से स्थापित करने में मदद करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

इसके बजाय, प्रियंका गांधी ने पंजाब में के सी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल, रंधावा और अन्य लोगों के बीच बने मजबूत गठजोड़ को सफलतापूर्वक तोड़ दिया है, क्योंकि ये लोग न केवल एक-दूसरे की मदद करते थे, बल्कि उनके कुछ कमर्शियल हित भी जुड़े हुए थे।

पंजाब के नेता बड़े दांव लगाने वाले खिलाड़ी हैं और बड़े पैमाने पर पैसों के खेल में शामिल रहते हैं।

सचिन पायलट के लिए यह एक महत्वपूर्ण और हाई-प्रोफाइल जिम्मेदारी है, जिसका असर राजस्थान में उनके भविष्य पर भी पड़ेगा।

पंजाब में जीत उनके राजनीतिक करियर के लिए चमत्कारिक साबित हो सकती है!!

"नाराज़ फूफा जी" तो हमेशा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की परियोजना की कल्पना 2004 में की गई थी, लेकिन, 2014 में भाजपा के सत्ता में आने तक, कुछ भी आगे नहीं बढ़ा।

किसी का नाम लिए बिना, प्रधानमंत्री ने फिर उन लोगों पर तंज किया, जो इस परियोजना की उपयोगिता पर सवाल उठा सकते हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, एक नाराज फूफा जी चिल्ला रहे होंगे कि "ट्रक ड्राइवर क्या करेंगे?" अब फूफा जी के पास भी काम है।"

उन्होंने कहा कि यह माल ढुलाई गलियारा उन जगहों तक रेल संपर्क पहुंचा रहा है, जहां आजादी के बाद भी रेल संपर्क नहीं था। उन्होंने कहा कि यह परियोजना आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए भारतीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने की व्यापक कोशिश का हिस्सा है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर एक और कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 2014 के बाद भारत ने 50 हजार आधुनिक रेलवे कोच बनाए, जबकि पिछली सरकार 10 साल में 50 हजार शौचालय भी नहीं बना सकी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब मैन्युफैक्चरिंग के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, "चिप से लेकर शिप (जहाज) तक", जिसमें कलपुर्जों से लेकर तैयार उत्पादों तक का निर्माण देश में ही किया जा रहा है।

"नाराज फूफा जी" प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आलोचकों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले व्यंग्यात्मक नामों की बढ़ती सूची में सबसे नया है। उन्होंने पहली बार पिछले सप्ताह श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। उस कार्यक्रम में उन्होंने युवा मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए अपने भाषण में जेन ज़ी की भाषा और शब्दों का भी इस्तेमाल किया था।

उस कार्यक्रम में उन्होंने उन लोगों पर निशाना साधते हुए यह उदाहरण दिया था, जिन्होंने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की उम्मीद से बेहतर, 7.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि "नकारात्मक सोच वाले लोगों" ने सरकार की पहलों का विरोध करना एक तरह का खेल बना लिया है।

उन्होंने कहा था, "कैंपस के बाहर आपको दो तरह के लोग मिलेंगे: एक वे, जो समाज की शक्ति को राष्ट्र की शक्ति में बदलने के लिए सकारात्मक रूप से काम करते हैं और दूसरे वे, जो किसी भी काम की शुरुआत होते ही "नाराज फूफा" बन जाते हैं।"

इस टिप्पणी से नाराज विपक्षी नेताओं ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि वे हर साल सरकार की कमियों से ध्यान हटाने के लिए एक नया विशेषण लेकर आते हैं।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जैसे मुद्दों को शामिल किए जाने की संभावना है। लॉजिस्टिक्स से जुड़ी बाधाओं को कम करने के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग जैसी संपर्क परियोजनाओं की भी समीक्षा की जा सकती है, ताकि माल ढुलाई से जुड़ी बाधाओं को कम किया जा सके।

यह बातचीत 31 अगस्त 2026 को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की हालिया मुलाकात पर आधारित है। उस दौरान मोदी और पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा की थी। मोदी ने "लगातार चलने वाले युद्धों से युद्ध की समाप्ति की ओर" बढ़ने की जरूरत पर जोर दिया था और शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के समर्थन को दोहराया था। दोनों नेताओं ने ऊर्जा आपूर्ति, एस-400 की डिलीवरी सहित, रक्षा संबंधों और व्यापक सहयोग की भी समीक्षा की थी। मोदी ने पुतिन को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों वाले विस्तारित समूह के नेता और साझेदार देश शामिल होंगे। इस 11 सदस्यीय समूह में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और यूएई शामिल हैं। पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद समेत, कई अन्य नेताओं के इसमें शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है या उनके आने की उम्मीद है। शी जिनपिंग 2019 के बाद पहली बार भारत आएंगे। भारत की अध्यक्षता में होने वाला यह शिखर सम्मेलन "लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण" विषय पर आधारित है और भारत-रूस संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक अवसर प्रदान करता है।

सत्य निकेतन की बगल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पास होना और बहुत अधिक आबादी, इसे बड़े भूकंप के लिहाज से खास तौर पर संवेदनशील बनाती है।

सत्य निकेतन की इमारत गिरने की घटना ने उन कई कमज़ोरियों को सामने ला दिया है, जो भूकंप को बड़े पैमाने की शहरी आपदा का रूप दे सकती हैं।

अधिकारी अब सार्वजनिक उपयोग वाली इमारतों और पीजी आवासों की संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) जाँच तथा सुरक्षा के नए उपायों पर विचार कर रहे हैं।

दिल्ली की इमारतों की जटिलता एवं बहुत बड़ी संख्या को देखते हुए यह चिंता और भी गंभीर हो जाती है।

"नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी" के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किये गए एक शोध-पत्र में, जो 2026 में एनवायरनमेंटल अर्थ साइंसेज में प्रकाशित हुआ, अनुमान लगाया गया था कि दिल्ली-एनसीटी में करीब 89 लाख इमारतें हो सकती हैं। अध्ययन में पाया गया कि इस इलाके में मुख्य फॉल्ट्स के पास मध्यम तीव्रता के भूकंप की स्थिति में करीब 38 प्रतिशत इमारतें असुरक्षित सिद्ध हो सकती हैं।

रजत पसरीचा, कपिल मोहन और ओ पी मिश्रा द्वारा किए गए इस अध्ययन में 6.0 तीव्रता के भूकंप की स्थिति में संभावित नुकसान का विशेष रूप से आकलन किया गया। इसमें आबादी का अधिक घनत्व, पुरानी इमारतें और स्थानीय भूगर्भीय स्थिति की जटिलता को बड़े जोखिम वाले प्रमुख कारण बताया गया है।

इसका मतलब यह नहीं है कि दिल्ली की 38 प्रतिशत इमारतें जरूरी तौर पर गिर जाएंगी।

भूकंप से होने वाला नुकसान इस बात पर निर्भर करता है कि भूकंप कहां आता है, उसकी गहराई और उसकी प्रकृति क्या है, स्थानीय मिट्टी की स्थिति कैसी है और अलग-अलग इमारतों की गुणवत्ता तथा डिज़ाइन कैसी है। लेकिन अध्ययन के निष्कर्ष दिल्ली के जोखिम के स्तर को उजागर करते हैं।

इसलिए दिल्ली के सामने चुनौती अगले भूकंप की भविष्यवाणी करना नहीं है। चुनौती यह है कि भूकंप आने से पहले शहर को उसके लिए तैयार किया जाए।

आतंकी कैंप आयोजित करने के आरोपी, सात विदेशी नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट

नई दिल्ली, 08 सितंबर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने और उग्रवाद से संबंधित कैंप आयोजित करने जैसे गंभीर आरोपों में शामिल एक अमेरिकन सहित, सात विदेशी नागरिकों के मामले में मंगलवार को चार्जशीट दाखिल की है।

एनआईए ने आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 यूएपीए की धारा 18 लगाई थी। खास बात है कि चार्जशीट में सभी आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धारा हटाई गई है।

चार्जशीट में केवल इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 21 और 23 लिखी है। धाराओं में ये दोनों धाराएं फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के स्तर पर समझौता योग्य (कंपाउंडेबल) अपराध की श्रेणी में आती हैं।

मजदूरों से भरी बोलेरो को ट्रक ने टक्कर मारी, 6 की मौत

बालाघाट भोपाल, 08 सितंबर। महाराष्ट्र के गोंदिया ग्रामीण थाना क्षेत्र में गोंदिया-बालाघाट मार्ग पर नागरा गांव के पास सोमवार की दरमियानी रात मजदूरों से भरी बोलेरो को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक तीन साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। इस हादसे में सात मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें गोंदिया के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी मृतक और घायल बालाघाट के रहने वाले हैं।

■ गंभीर रुप से घायल 7 मजदूरों को गोदिया के जिला अस्पताल में भर्ती कराया।

बालाघाट जिले ये लोग मजदूरी करने के लिए बोलेरो वाहन से हैदराबाद जा रहे थे। इसी दौरान सोमवार की रात करीब 12 से एक बजे के बीच महाराष्ट्र के गोंदिया ग्रामीण थाना क्षेत्र के नागरा में यह हादसा हो गया। मजदूरों से भरी बोलेरो गाड़ी को सामने से आ रहा एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। ट्रक को क्रेन की मदद से हटाया और बोलेरो में फंसे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। बोलेरो में चालक के अलावा कुल 13 लोग सवार थे, जिनमें से पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची ने बाद में दम तोड़ दिया।

दिल्ली महापौर कार्यालय को नवीं बार बम से उड़ाने की धमकी मिली

पूरे कार्यालय परिसर के सघन तलाशी अभियान में कुछ भी अवांछनीय नहीं पाया गया

नई दिल्ली, 08 सितंबर। दिल्ली के महापौर कार्यालय को मंगलवार को एक बार फिर बम विस्फोट कर उड़ाने की धमकी मिली। महापौर कार्यालय ने तत्काल सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद महापौर कार्यालय परिसर और आसपास के इलाकों की सघन तलाशी के लिए अभियान चलाया गया। यह नौवीं बार है, जब महापौर कार्यालय को इस प्रकार की धमकी मिली है।

■ लगातार प्राप्त हो रही धमकियों के बाद महापौर कार्यालय ने पुलिस आयुक्त को औपचारिक पत्र लिखकर प्रभावी कार्यवाही की मांग की है।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, पुलिस एवं संबंधित सुरक्षा एजेंसियों ने महापौर कार्यालय परिसर की सघन तलाशी अभियान के दौरान प्रत्येक संवेदनशील क्षेत्र, प्रवेश एवं निकास द्वार तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की गहन जांच की। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे परिसर का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया।

महापौर कार्यालय ने स्पष्ट किया कि यह पहली बार नहीं है, जब इस प्रकार की धमकी प्राप्त हुई है। इससे पूर्व भी आठ बार महापौर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं।

लगातार प्राप्त हो रही ऐसी धमकियों को अत्यंत गंभीर विषय मानते हुए, महापौर कार्यालय द्वारा पूर्व में दिल्ली पुलिस आयुक्त को एक औपचारिक पत्र भी प्रेषित किया गया था, जिसमें इन घटनाओं की विस्तृत जांच कर दोषियों की पहचान करने तथा उनके विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था।

महापौर कार्यालय ने कहा कि सार्वजनिक संस्थानों एवं संवैधानिक पदों से जुड़े कार्यालयों को बार-बार इस प्रकार की धमकियां मिलना चिंता का विषय है। ऐसे मामलों में दोषियों की शीघ्र पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई किया जाना आवश्यक है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की शरारतपूर्ण एवं भय उत्पन्न करने वाली घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908